Functioning of core industrial sector

3581. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of PLANING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what step has been taken by Government to ensure smooth functioning of the core industrial infrastructural sectors;

(b) what are the bottlenecks faced by some of the sectors; and

(c) what corrective measures have been suggested to concerned administrative Ministries to remove the bottlenecks?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) The performance of the core industrial infrastructural sectors is closely monitored at various levels in the Government to ensure their smooth functioning.

(b) The bottlenecks faced by some of the core sectors are as follows:

(i) Petroleum . .	Technical factors
(ii) Railways . .	Resource crunch
(iii) Power . . .	Financial constraints

(c) The corrective measures to tide over the bottlenecks arising out of technical reasons are applied by the concerned administrative Ministries and the operational problems of cooddination are reviewed periodically and accordingly addressed to.

समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना

3582. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :
क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री 27 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 1837 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं किए/जा रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों के उद्देश्य क्या है ;

(ग) ये उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए हैं;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना के अंतर्गत रखे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) मध्य प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्र और स्थान इससे लाभान्वित होंगे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना केन्द्र (सीआईआरईपी) की स्थापना बकोली, दिल्ली मे की गई है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग की तकनीकी और वित्तीय सहायता से बंगलोर (कर्नाटक), शिलांग (मेघालय) लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा खेडा (गुजरात) में चार और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है ।

(ख) इन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा विकास आई आर ई पी केन्द्रों के उद्देश्यों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर संबंधी प्रशिक्षण देना और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप आयोजित करना शामिल है ।

(ग) दिल्ली में स्थापित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र ने मार्च, 1990 से कार्य करना शुरू कर दिया है । जुलाई, 1992 तक केंद्र में 49 प्रतिशत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है । एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना केन्द्र, लखनऊ ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है ।

और विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों तथा संबंधित कार्यकलापों का आयोजन करना शुरू कर दिया है ।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का लगभग 100 ब्लाक प्रति वर्ष की दर से विस्तार करने का प्रस्ताव है । राज्य जिला और निम्न स्तरों पर एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमताओं के विकास के विद्यमान केंद्रीय प्रायोजित घटकों के अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के लोगों को खाना पकाने और रोशनी की न्यूनतम घरेलू ऊर्जा आवश्यकतायें प्रदान करने के लिए एक नया घटक एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में जोडने का प्रस्ताव है । 1991-92 तक मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम 21 ब्लाकों में शुरू किया गया है । मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में चुनिंदाय ब्लाकों में कम से कम एक ब्लाक स्तरीय एकीकृत ऊर्जा ग्रामीण परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

3583. [*Transferred to 20th August, 1992*].

मध्य प्रदेश में कम विकास दर होना

3584. **श्री अजीत जोगी :**
श्रीमती कैलाशपति :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की विकास दर अन्य राज्यों की विकास-दर तुलना में कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों की वार्षिक समेकित विकास दर और राज्यवार वार्षिक विकास दर कितनी-कितनी थी ; और

(घ) मध्य प्रदेश की विकास दर को बढाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के स्थिर मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद और अखिल भारतीय निवल घरेलू उत्पाद की राज्यवार वार्षिक विकास दरों को दर्शाने वाला एक विवरण (**नीचे देखिए**) संलग्न है । अनेक कारणों से राज्यों के बीच विकास दरें भिन्न-भिन्न होती हैं, उनमें से कुछ विभिन्न क्षेत्रों में आधारिक संरचना उद्योग तथा उद्यमशीलता के ऐतिहासिक रूप से असमान विकास के कारण तथा वर्षों में वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तन एवं अनुवर्ती सूखा तथा बाढ के कारण होती है ।

(घ) विकास दर में वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं । इन योजनाओं में कृषि, उद्योग आधारिक संरचना, सिंचाई ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास के लिए निवेश शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, गरीबों के लिए सीधा रोजगार एवं आय उत्पन्न करने के लिए कुछ कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है । आठवीं पंचवर्षीय योजना (19-92-97) के दौरान कुछ विकास कार्यक्रमों को पुनः लागू किया जाएगा । आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत परिव्यय 11,100 करोड़ रुपए है ।